میں نہیں ہو رہا ہے ۔ دانا پور سے باہر
ریلوے کالونیز میں الگ ہو رہا ہے ۔[†]

और हिंदुस्तान भर में गलत रास्ते पर चला जा रहा है। क्या रेलवे मिनिस्टर साहब यह कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट के मकानात है, उनमें जितने मकानात पुराने हो चुके हैं, उनकी जगह धीरे-धीरे नये मकान बने और आप्टीमम लैंड यूज हो?

[†]شری سکندر بخت "جاری": اور ہندوستان
بھر میں غلط راستے پر چلا جا رہا ہے ۔ کیا ریلوے
منسٹر صاحب یہ کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ
کے مکانات ہیں ۔ ان میں جتنے مکانات
پرانے ہو چکے ہیں ان کی جگہ دھیرے دھیرے
نئے مکان بنیں اور "آپٹیمم لینڈ" یوز ہو[†]

श्री राम विलास पासवान: मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं और मुझे लगता है कि कुछ मकान हैं जो नये बनाये जा रहे हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा। इन्होंने कहा कि जो लार्ज सिटीज में बिल्डिंग्स बन रही हैं वे मल्टी-स्टोरीज बन रही हैं। इसलिए जो फेजवाइज में करने की बात है, हम इस बात को करेंगे।

Completion of Konkan Railway Project

*242. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the details of completion of Konkan Railway Project and what is the total cost of the project as per the present estimate; and

(b) by when Konkan Railway Project will be completed and commissioned?

(रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 760 कि॰मी॰ में से अभी तक 229 मार्ग किलोमीटर लाइन को यात्री यातायात के लिए खोला गया है और अन्य 460 कि॰मी॰ लाइन लगभग तैयार है। मार्च, 1996 के अनुमान के अनुसार इस परियोजना की लागत 2230.42 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, कोंकण रेलवे को दिसंबर, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam Deputy Chairman, this 760 km. single track Konkan Railway Project comprises 382 kms. in Maharashtra, 273 kms. in Karnataka, and 105 kms. in Goa. This project has 145 major bridges and 1670 minor bridges. It also has 81 tunnels; the length of the largest tunnel is 6.5 kms. These tunnels pass through a difficult terrain. In fact, Madam, this project is a challenge to the expertise of our planners and engineers.

The Konkan railway line passes through three States. A number of industries are coming up, worth about Rs.50,000 crores. In Karnataka alone, in my district, i.e. Dakshina Kannada, a number of projects—steel plants, power projects and refineries—are coming up. The entire nation is waiting for the speedy completion of this prestigious project.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it looks as if he is replying to the question as a Minister.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam, the original deadline fixed for the completion of this project was March, 1994. It was extended and another deadline was fixed, i.e. December, 1995. The hon. Minister, while presenting the Railway Budget on 16th July, 1996, fixed the deadline for the inauguration of traffic as October, 1996. However, Mr. Minister, in the reply given today, within a matter of ten days, your Department has changed the deadline. You now say that it will opened for traffic in the month of December, 1996. You say that you have difficulties; financial as well as technical. May I know from the hon. Minister whether, in regard to finance, he has tied up with the Planninng

†[ ] Transliteration in Arabic script.

Commission and the Finance Ministry? What is the quantum of additional resources you require? I would like to know whether you are going to enter the capital market for mobilising additional resources for the completion of this project.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि जो हमारी प्रगति है वह 95 परसेंट तो हमारी प्रगति हो गई है, सिर्फ 5 परसेंट बची है। यदि आप देखेंगे तो मेरे पास सारे आंकड़े हैं। भूमि अधिग्रहण 100 परसेंट, मिट्टी का काम 100 परसेंट, 1819 छोटे पुलों में से 1800 छोटे पुलों पर काम खत्म हो गया है। सिर्फ तीन पुल का काम चल रहा है। 179 बड़े पुलों में से 178 पुलों पर काम हो गया है, सिर्फ एक पुल बचा है 83,400 किलोमीटर में से 82,349 किलोमीटर में टनल बनाने का काम भी पूरा हो गया है, 801 किलोमीटर में से 656 किलोमीटर में रेल ट्रैक का जोड़ने का काम हो गया है। जो स्टेशन की इमारते हैं 56 में से 48 वह भी हो गया है। सिगनल और दूर संचार संबंधी काम भी 47 में से 46 स्टेशनों पर पूरा हो गया है। अब जो मामला है इसमें जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें हमको कुल मिला करके जो रकम की आवश्यकता है वह तीन सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उस तीन सौ करोड़ रुपये में से जो एक सौ करोड़ रुपया था वह बैंक आफ् अमेरिका से आना था और उसमें से ज्यादा भी पैसा वहां से आने की संभावना है। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारा बजटरी सपोर्ट वगैरह कुछ बढ़ जाए, आंतरिक साधन हमारा मजबूत हो जाए तो हम उससे करें लेकिन हम उसी के लिए आल्टरनेटिव उपाय भी सोचे हुए हैं और उसमें जो प्राब्लम था लैटर आफ् कैफर्ट का वह रेलवे मंत्रालय ने बैंक आफ् अमेरिका को दे दिया है और उसके बाद कोंकण रेलवे का जो सी॰एम॰डी॰ है वह एक-दो- दिन के अंदर में सिंगापुर और लंदन कहते हैं कि जा रहे हैं और हमको लगता है कि 15 अगस्त तक पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। यह जो आपने लिखा गया है इसको मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि वह कार्पोरेशन है, आप माननीय सदस्य जानते हैं कि रेलवे का नहीं है वह कार्पोरेशन के माध्यम से है उसने अलग-अलग जो पैसा इक्विटी से, बांड से जहां-जहां से आना है उनके ऊपर में हमको निर्भर करना पड़ रहा है। लेकिन हम अपने स्वयं चिंतित हैं, चूंकि इस में एक दिन में 40 लाख रुपया इन्टरेस्ट में जा रहा है। तो जो बैंक का सूद है उसमें 40 लाख रुपया प्रतिदिन जा रहा है। इससे ज्यादा चिंता की बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपने बजट भाषण में कहा है कि अक्तूबर तक में मालगाड़ी चल जाएगा, और दिसंबर में पैसेंजर गाड़ी चल जाएगा आज भी मैं उसी पर कायम हूं।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam, there is some difficulty with the mud embankment of the railway track along the Zuari river in the Goa sector.I am told there is a representation and that the Railway Minister has...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Fernandes's name is also there.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Due to the monsoon, the mud embankment has sunk, creating trouble for the farmers and also for the railwaymen. The construction work is delayed, a lot of damage has been caused and the people of Goa are worried about it. I would like to know whether it is difficult for the Konkan Railway authorities to overcome this difficulty, particularly with the advanced technology that has been adopted by them. All along a three-kilometre route they are facing this mud problem. May I know from the hon. Minister whether he has found some solution to this problem and whether he is going to satisfy the people of the Goa sector which has got 105 kilometres of track at one stretch? I would also like to know from the hon. Minister when he is going to inaugurate the other sector, which marks completion of the entire Konkan Railway project, which is the lifeline for the economic development of the backward area of western coastal India.

श्री राम बिलास पासवान: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि जो जगह-जगह पर जमीन का मामला है, नीचे में जो पत्थर हैं, इनके कारण काफी बाधाएं आ रही हैं और अभी भी कुछ दिन पहले एक टनल के गिरने का समाचार आया। मैंने कल ही उसकी जांच करवाया। वह असल में खुशी की बात है कि वह टनल नहीं था, टनल के बगल में

जो उसका शैड वगैरह बनाया गया था तो वह है, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि जो हमारे इंजीनियर हैं और खास करके हमको लगता है कि सी०एम०डी० हैं तो उनके पहली बार ऐसा एक सी०एम०डी० है जिसके खिलाफ में इस तरह का कोई चार्ज नहीं आया है। वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे है। उपसभापति जी, मैं स्वयं एक्सटेंशन के खिलाफ रहता हूं। अभी रेलवे बोर्ड के चैयरमैन का टर्म पूरा हो रहा था, उन के बदले दूसरे को लाया गया है, लेकिन सी०एम०डी० को जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता है, टर्म बढ़ाने का आदेश दिया गया है। तो समस्याएं हैं, लेकिन वह समस्या नहीं है। हमारे पास पैसे की समस्या है। अगर हमारे पास 300 करोड़ रुपया आ जाय तो मैं आप को आज कह सकता हूं कि मैं स्वयं 31 अक्तूबर को जाकर उस का उद्घाटन कर दूंगा। इसलिए हमारी जो फायनेंसियल प्राब्लम हैं, उस को हल करने के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की है।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, the main problem with the Konkan Railway, especially in the Goa sector, is non-planning. They have not planned that properly. A Corporation was created, and a lot of money was given in the hands of that Corporation. It was not farsightedness. I have raised it off and on in this House. Nobody opposes the Konkan Railway. The dispute is that 50 km. of this Railway, which was passing through the mining sector, has been diverted from the hinterland to the coastal area. As a result, you cannot complete this Project because the soil is alluvial. This is kazan land and mangrove land, and no plling has been done.

The Government appointed the Oza Commission and the Commission has given some recommendations for implementation by the Konkan Railway Corporation. The Government of India has made it top secret, and it has not been made public. As a result, we have the problem stated by Mr. Poojary. A dump merged in the alluvial soil, and there is a blockade. I want to know from the hon. Minister whether he will use the latest foreign technology to build these tunnels which are collapsing again and again, whether he will make the recommendations of the Oza Commission to protect the environment public and whether he will lay this report on the Table of the House.

Thank you.

श्री राम विलास पासवानः उपसभापति जी, यह जो माननीय सदस्य ने कहा, अब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि केवल 1005 मीटर का कार्य पूरा करने के लिए बचा है। अब मैं पुरानी बात पर नहीं जाऊंगा कि उस को चेंज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वह पुरानी बात हो चुकी है। अब हमारे सामने मुख्य समस्या यह है कि हम किस तरीके से इस परियोजना को पूरा करें। दूसरी चीज जो कमेटी के संबंध में इन्होंने कही है, हम उस कमेटी की रिपोर्ट को जरूर देखेंगे। असल में आज हमारी लोक सभा सुबह साढ़े 7 बजे तक चली है। यह ओझा कमेटी की जो रिपोर्ट है हमारी, दूसरी की तो सिफारिश मेरे सामने है जो रहमान कमेटी बनी थी, लेकिन मेरे पास अभी वह नहीं है। यह हमारे पास आई है—

The line has not been diverted. The adjustment has been selected after a survey. It has been upheld by the Oza Commission. we are using the latest technology. उस की रिकमंडेशन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उन को भेज दूंगा।

SHRI JOHN F. FERNANDES: The Railways have already deposed before the Oza Commission. They selected the bridge before they did the alignment to help some companies. Why is the Minister misguiding us? It is before the Oza Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said that he received the Oza Commission Report.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I understand, Madam,..

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has said that the Oza Commission Report has accepted that they are using the best technology.

SHRI JOHN F. FERNANDES: It is not being implemented, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If they are using the best technology, how is it not being implemented?

SHRI JOHN F. FERNANDES: Then the problem, as Mr. Poojary has stated, would not have arisen.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Perhaps, the Member wants to know the recommendations made by the Oza Commission.

ओझा जी ने कहा है कि 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी जगह पर तटबंधों के स्थान पर पुलिया का निर्माण किया जाए। बाढ़ के पानी की निकासी की अतिरिक्त व्यवस्था हो तथा .... **(व्यवधान)**...क्षेत्र में मछुआरों के लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए। कतिपय स्थानों पर ... **(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, he is saying that.

SHRI JOHN F. FERNANDES: They are not adhering to the recommendations. Therefore, we have this problem in this whole thing in Goa.

श्रीराम विलास पासवान: आप का प्रश्न था कि क्या आप औझा कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करने जा रहे है या नहीं? आप ने कहा कि यह सीक्रेट है। यदि मेंबर इंटरेस्टेड है कि क्या उस की रिपोर्ट है तो मैं अभी उस को पब्लिक कर सकता हूं। यदि आप डिटेल्ड में चाहते हैं तो हम आप के पास भेज देंगे।

उपसभापति: नहीं, मंत्री जी, यह सवाल नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ओझा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट केआधार पर, उनकी रिकमण्डेशन के आधार पर, जो बाकी का प्रोजेक्ट बचा है, जहां आपको बाधा आ रही है, तकलीफ आ रही है, जहां कही गिर रहा है, आप उसकी रिकमण्डेशन का सहारा लेकर उसको इंपलीमेंट करने की कोशिश कर रहे है? सवाल इतना है।

श्रीराम विलास पासवान: ओझा कमेटी की रिपोर्ट को हमने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और इसको हम इंपलीमेंट कर रहे हैं। इसलिए यह अगर, मगर, लेकिन कुछ नहीं, इफ, बट कुछ नहीं, पूरा का पूरा।

श्री के० रहमान: मैडम।

उपसभापति: अभी तो सब वह कम्पलीट हो गया 1000 मीटर खाली रह गया। रहमान साहब, अब यह 1000 मीटर के लिए कुछ पूछ रहे है? दूसरा सवाल इम्पोर्टेण्ट है, वह लेते है।

श्री के० रहमान: मैडम, यह इम्पोर्टेण्ट सवाल है। मैं यह 600 मीटर का नहीं पूछ रहा हूं। Madam, it has been said by other Members also that the Parliament has been assured that this Konkan Railway Project will be completed in December 1995, March 1996 and now it is December 1996 again. The hon. Minister has said that he requires about Rs. 300 crores. When the Railway has already spent Rs. 22 crores and every day it is spending Rs. 40 lakhs as interest, which will be about Rs. 12 crores every month, I do not think it is difficult for the Government of India to arrange Rs. 300 crores from the natinalised banks even by paying a high rate of interest to reduce the cost. I think arranging Rs. 200 crores or Rs. 300 crores is not a problem as far as the Konkan Railway is concerned. Madam, the project

has been delayed because of the tunnels. I would like to know how much distance of tunnel has been completed and what is the balance which is yet to be completed, because the work on the tunnel is very slow.

Part (b) of my question is whether the Railway Board has accepted the recommendation of the MPs, which has submitted its report to the Government?

श्री राम विलास पासवान: मैंने पहले ही बतला दिया था, पूरा आंकड़ा दे दिया था। यह केवल 1000 मीटर जो है वह टनल, क्या कहते हैं कि, बचा हुआ है। जो आपने कहा, संसदीय समिति के संबंध में आपने कहा, रहमान साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी बनी थी। इसमें दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा कोंकण रेलवे के कार्यकरण के कतिपय पहलुओं, भूमि देने वालों को क्षतिपूर्ति के भुगतान, भूमि देने वालों को रोजगार, सड़क क्रोसिंग तथा लैंड डीमार्केशन के कारण अवरुद्ध हुए निकासी मार्गों की पुनः स्थापना, कोंकण रेलवे निगम परिसंविदा, प्रबंधन आदि के संबंध में शिकायतें की गई थी और इन पहलुओं की जांच करने के लिए वह समिति

बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। उन सभी सिफारिशों पर अमल करने के लिए कोंकण रेलवे निगम को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि जल्द से जल्द उसको कार्यान्वयन करके रिपोर्ट दें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I sympathise with the Railway because the basic problem of funding the Railway plan is that they are to depend more and more on raising resources from the market. In fact, most of the years, the Railway has not been able to raise the resources through bonds. While replying to the main question, the hon. Minister has said that he would require an additional Rs. 300 crores to complete the project. I would like to know what would be the component of the Budgetary support of Rs. 300 crores and what would be the component of the resources raised through the market.

Secondly, I would like to know about the figure which he has quoted, Rs. 40 lakhs. If it is Rs. 40 lakhs per day, that means Rs. 140 crores per year is the interest liability, which you are paying. Therefore, the relevance of raising the resources through bonds is more important. So, I would like to know its break-up. In this connection, while presenting the General Budget, the Finance Minister had said that in the course of the year he will meet the requirement of the railways, so far as the Plan Budget is concerned. I would like to know whether the Konkan Project is included in the expected support in future through the Budgetary role.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, अभी तक हमको 500 करोड़ रुपए से अधिक का एक एक्सट्रा बर्डन पड़ गया है उसके इंटरेस्ट में, जो हमने कर्जा लिया है और आप माननीय सदस्य जानना चाहते थे इसकी ब्रेक-अप, तो 600 करोड़ रुपया जो, उसमें से 596 करोड़ रुपए इक्विटी से प्राप्त हुए हैं और उसके अलावा 1466 करोड़ रुपए बांड्स से प्राप्त हुए हैं और जो इक्विटी से प्राप्त हुए हैं उसमें 51 परसेंट वह है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल की जो सरकारें हैं, 49 परसेंट उनका शेयर है और 1466 करोड़ रुपए बांड्स से प्राप्त हुए हैं और 78 करोड़ रुपए बड़ी सम्पत्ति की बिक्री और पट्टा देने से प्राप्त हुए हैं। तो इसको कुल मिलाकर काटने से 300 करोड़ के करीब उसके लिए बचता है, जिसको संसाधन की जरूरत है और इसके लिए मैंने कहा कि हमारे सी०एम०डी० विदेश जा रहे हैं पैसा लेने के लिए और हम भी उसमें कोशिश करेंगे कि हमको 300 करोड़ रूपया पूरा का पूरा मिल जाए। यदि पूरा पैसा मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि कम पैसा मिलेगा तो हम तो मांग ही रहे हैं कि बजटरी सपोर्ट बढ़ाई जाए, प्रधान मंत्री से भी आग्रह कर रहे हैं और भारत सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं लेकिन हमारी कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से पैसे के अभाव में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नहीं रोका जाए। प्रोजेक्ट को रोकने से सिर्फ प्रोजेक्ट का ही डिले नहीं हो रहा है बल्कि उससे हमारे ऊपर जो दिन-प्रतिदिन बोझा पड़ता जाएगा, वह हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा, कारपोरेशन के लिए, उसको पे करना।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam Deputy Chairman, the Minister is really optimistic. But I do not find any reason to become as optimistic as the Minister of Railways is. The main factor is or the main factors are: there has been time overrunning and cost overrunning. Those are the basic causes for the extra financial burden being imposed. There was no proper technological evaluation of the project. Therefore, Madam, I would like to know from the Minister whether he is aware that implementation of the project got unnecessarily delayed because there was a constant interference from above in the work and there was no coordination betweeen the Konkan Railway authorities and the Ministry of Railways to the extent that even a Committee of Members of Parliament was constituted to look into the affairs at a particular point of time. Is he aware of that? If so, would he take proper care to ensure that no such interference is there? This is (a) part. Part (b) is: He is expecting a large sum from the Bank of America. I do not know what he rate of interest being charged by them is. Part

(c) is: Why has he to run to Washington or to the Bank of America for Rs. 100 crores? Why is it not possible for him to find the money from Indian banks, Indian financial institutions, and, above all, from the public?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, 15 अक्तूबर, 1990 को इस कोंकण रेलवे निगम ने कार्यभार संभाला था और उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि पांच साल में यह कार्य पूरा हो जाएगा बल्कि यह कहा गया था कि चार साल में ही इसको पूरा कर लिया जाएगा. जब भाषण हुआ था उस समय के तत्कालीन रेलवे मंत्री जी का तो उन्होंने इसे पांच साल से घटाकर के चार साल कर दिया था। पांच साल के हिसाब से भी इसे 1995 में पूरा हो जाना चाहिए था. उसके बाद यह कहते हैं कि अब 6 साल हो गया है. जहां तक संसदीय समिति की रिपोर्ट का सवाल था, मैंने अभी उसको पूरी डिटेल में बतलाया है. अब बैंक का जहां तक सवाल है, बैंक के संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है— सतीश अग्रवाल जी है, प्रणव बाबू हैं और मनमोहन सिंह जी हैं, जो इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं— लेकिन हमको बतलाया गया है कि जिस बैंक से हम पैसा लेना चाहते हैं, बड़ी सस्ती दर पर पैसा वहां से मिल रहा है और यदि अपने बैंकों से लेंगे तो बड़ी भारी दर पर पैसा मिलेगा. इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से पैसा लिया जाए.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It means the Railway Board believes that foreign banks are more generous.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, that question is over. There was a lot of discussion over that question. Now, Q.No. 243..*(Interruptions)*...

Sale of synthetic milk

*243. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sale of synthetic milk has come to the notice of Government in certain areas of the country;

(b) if so, the States in which this has come to light; and

(c) what action Government have taken to deal with this crime?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) तथा (ख) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से दूध में बाहरी तत्वों की मिलावट होने के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ग) मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक लगी हुई है तथा खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली, 1955 के उपबंधों के अधीन यह एक दण्डनीय अपराध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों ने अपने निगरानी उपायों को तेज कर दिया है तथा अपराधियों के विरूद्ध अभियोजन के मामले आरंभ कर दिए हैं। सरकारी/सहकारी समितियों के स्वामित्व वाले डेयरियों ने अपने गुणवत्ता परीक्षण तंत्र को सख्त कर दिया है तथा सभी पंजीकृत निजी डेयरियों को उनके संयंत्रों में मिलावटी दूध के प्रवेश को रोकने के द्वारा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam, I would like to point out that synthetic milk is manufactured and sold by private dairy plants in the country. Synthetic milk is used by the people in all the countries. The ingredients used in the manufacture of synthetic milk are synthetic soda and water and some salt. That salt is from foreign countries. Synthetic milk will directly affect children, Madam. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether any steps have been taken to prevent the production and sale of synthetic milk. In June, 1992, the then Agriculture Minister had enacted the Milk and Milk Products Act. Has that Act been enforced or not? As per that Act, all the private dairy plants in the country must be registered before the forum meant for it and must give full particulars regarding the place of manufacture and supply and private milk vendors. I would like to know whether any special steps are going to be taken to prevent the production and sale of synthetic milk. Or, is there any new law or new Bill proposed to be introduced in regard to the production and sale of synthetic milk?